अनिलजीत सिंह त्रेहन-आवेदक,

बनाम

एम. डी. विश्वविद्यालय और अन्य,-प्रतिवादी।

1989 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 1804।

22 दिसंबर, 1989.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 14—मेडिकल कॉलेज में प्रवेश–पूर्व सैनिकों के लिए सीटों का आरक्षण–अधिकारियों के बच्चों और जे.सी.ओ. के बच्चों के बीच उप-वर्गीकरण–ऐसा उप-वर्गीकरण–क्या भेदभावपूर्ण है।

माना गया कि उपविभाजन मनमाना नहीं है। यह अत्यंत उचित है. अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी में निहित निष्पक्षता की व्यापक अवधारणा राज्य को समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखने और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित या विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई करने का आदेश देती है। वास्तविक समानता लाने के लिए, उन्हें अधिक लाभप्रद रूप से रखा गया है। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, हालांकि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है, वास्तविक असमानताओं को खत्म करके और समुदाय के कमजोर वर्ग को अधिक शक्तिशाली वर्ग के साथ समानता के आधार पर रखकर व्यापक आधार पर समानता उत्पन्न करने के लिए गणना की जाती है ताकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपनी प्राकृतिक संपदा का पूरा उपयोग करने के समान अवसर का आनंद लें।

(पैरा 6)

माना गया कि यदि अवधारणा ओ| अनुच्छेद 14 में व्याप्त निष्पक्षता का कोई अर्थ है, विवादित उप-वर्गीकरण को निष्पक्ष, उचित माना जाना चाहिए और इसका उद्देश्य दो वर्गों के बच्चों को अवसर की समानता प्रदान करना है। सिद्धांत और मिसाल दोनों ही आधार पर, इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व सैनिकों की श्रेणी में एक ओर अधिकारियों के बच्चों और दूसरी ओर जेसीओ और अन्य रैंकों के बीच उप-वर्गीकरण उचित है, निष्पक्ष और वैध, इस तरह के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ संबंध होना।

(पैरा 8 एवं 9)

एल.पी.ए. सी.डब्ल्यू.पी. में पारित 20 सितंबर, 1989 के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत। माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता द्वारा 1980 की संख्या 9242।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हरिओम शर्मा।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एल. गुप्ता और अधिवक्ता विक्रांत शर्मा।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वकील आर.के. मलिक।

निर्णय

न्यायमूर्ति ए. पी. चौधरी

(1) यह अपीलकर्ता की रिट याचिका संख्या 9242/1989 को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील है। उठाया गया एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या महर्षि दयानंद के तहत मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में सीटों के आरक्षण का उप-वर्गीकरण किया गया है। एक ओर अधिकारियों और दूसरी ओर जेसीओ और अन्य रैंकों के बीच पूर्व सैनिकों के बच्चों से संबंधित विश्वविद्यालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(2) अपीलकर्ता का बेटा संयुक्त पी.एम.टी. में उपस्थित हुआ। जून 1989 में एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक के तहत मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा। उन्होंने एक विकलांग सेना अधिकारी के बेटे की उप-श्रेणी के खिलाफ विचार किए जाने के लिए आवेदन किया। उनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया. इसलिए, उन्होंने एक ओर मृतक या विकलांग जेसीओ और अन्य रैंकों के बच्चों और दूसरी ओर मृत/विकलांग अधिकारियों के बच्चों के बीच आरक्षण के उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को प्रॉस्पेक्टस में, के निर्देशों के तहत चुनौती दी। आपकी सरकार.

(3) उत्तरदाताओं 1 और 2 की ओर से एम.डी. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर रिटर्न में, यह कहा गया था कि अपीलकर्ता ने प्रॉस्पेक्टस में अधिसूचित आरक्षण के आधार पर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और चयनित होने में असफल रहा था। पूर्व सैनिकों से संबंधित श्रेणी के उप-वर्गीकरण की वैधता को चुनौती। जेसीओ और अन्य रैंकों के बच्चों और अधिकारियों के बीच 2:1 के अनुपात को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई थी कि पहले वाले की संख्या बाद वाले की संख्या से कहीं अधिक थी। आरक्षण प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा किया गया था। आगे यह कहा गया कि अन्य सरकारी संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों में लागू नियम और कानून प्रासंगिक नहीं थे और एमडी विश्वविद्यालय उन अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। यह भी कहा गया कि उक्त उप-वर्गीकरण शैक्षणिक सत्र 1985-86 से बिना किसी चुनौती के अस्तित्व में था।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत उनके आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 9 को पक्षकार बनाया गया था। उन्होंने उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा दायर लिखित बयान में ली गई दलीलों को अपनाया और उनके द्वारा दायर लिखित बयान में यह भी जोड़ा गया कि वर्ष 1984-85 के प्रॉस्पेक्टस में 100 प्रतिशत आरक्षण था। जेसीओ के बच्चे; और पूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत अधिकारी के बहिष्कार के लिए अन्य रैंक। इसे एक अधिकारी की बेटी ने 1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 4491 में संविधान

के अनुच्छेद 14 और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। रिट याचिका को इस न्यायालय ने नवंबर में खारिज कर दिया था। 8, 1984. इसके बाद असफल याचिकाकर्ता ने 1984 की एसएलपी संख्या 1480 दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। दूसरे शब्दों में, अधिकारियों के बच्चों को छोड़कर, जेसीओ और अन्य रैंक के बच्चों के लिए पूर्व सैनिकों से संबंधित श्रेणी में 100 प्रतिशत आरक्षण की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। इसलिए, पूर्व सैनिकों से संबंधित श्रेणी में अधिकारियों के बच्चों के पक्ष में 83 प्रतिशत के मुकाबले जेसीओ के पक्ष में 86 प्रतिशत पीएस की सीमा तक वर्तमान आरक्षण पूरी तरह से वैध और उचित बताया गया था। आगे यह भी कहा गया कि अन्य रैंकों में जेसीओ की संख्या लगभग 99 प्रतिशत है, जबकि अधिकारियों की संख्या केवल 1 प्रतिशत या उससे भी कम है। यह बताया गया कि एक इन्फैंट्री बटालियन में कुल संख्या 1000 है, जिनमें से अधिकारियों की संख्या 10 है और जेसीओ और अन्य रैंकों की संख्या 990 है। उत्तरदाताओं ने जिला करनाल के पूर्व सैनिकों से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख किया। इन आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 1988 को जिले में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 21,151 थी और अधिकारियों की संख्या केवल 107 थी। इसलिए, यह कहा गया कि बच्चों के लिए 33 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण दिया गया था 1 प्रतिशत अधिकारियों का हिस्सा देय हिस्सेदारी से कहीं अधिक था और इसके अनुचित होने का कोई सवाल ही नहीं था। यह भी बताया गया कि अधिकारियों का न्यूनतम मूल वेतन रु. 2,300 जबकि अन्य रैंकों का न्यूनतम मूल वेतन रुपये था। 870. अधिकारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक थी। जेसीओ और अन्य रैंकों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिए, एक वर्ग के रूप में, जेसीओ और अन्य रैंक थे। अधिकारियों की तुलना में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। यह भी कहा गया कि सेना में अधिकारियों के लिए आवास 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध था, जबकि अन्य रैंकों के लिए आवास केवल 14 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध था। इसलिए, अन्य रैंक के 86 प्रतिशत लोग अपने परिवार को साथ नहीं रख सकते हैं, इस प्रकार पिता की उचित देखरेख और मार्गदर्शन के अभाव में उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। यह भी बताया गया कि उप-वर्गीकरण का पालन नहीं किया गया, वर्तमान प्रवेश में, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों में से 60 प्रतिशत अधिकारियों के बच्चों को और .40 प्रतिशत बच्चों को मिलेंगी।

बच्चों के दो सेटों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जेसीओ और पूर्व सैनिकों की।

(1) विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार किया कि यह प्रश्न कि क्या अधिकारियों और जेसीओ और अन्य रैंकों के बीच इस तरह का अंतर अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा बनाए रखा गया था, प्रासंगिक नहीं था, हालांकि चैल में एक सैन्य स्कूल द्वारा ऐसा अंतर देखा गया था। यह भेद शैक्षणिक सत्र 1985-86 से लागू था। और अपीलकर्ता ने मौजूदा आरक्षण के विरुद्ध चयनित होने के अवसर का लाभ उठाया था और मेरिट सूची में शामिल होने में विफल रहा, वह पलट नहीं सकता और आरक्षण को चुनौती नहीं दे सकता।

(2) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे सामने वही तर्क दोहराए। अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों में ऐसा उप-वर्गीकरण किया जाता है या नहीं, यह नीति का प्रश्न है। नीति को संबंधित उचित प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है और जाहिर तौर पर नीति न्यायालय द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। जब ऐसी कोई नीति तैयार की जाती है और उसे चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के आलोक में इसकी वैधता की जांच करनी होगी। कुमारी चित्रु घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, (1), एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार निर्धारित किया: -

"यदि स्रोतों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है, चाहे क्षेत्रीय आधार पर,

भौगोलिक या अन्य उचित आधार पर, वर्गीकरण करने के तरीके और पद्धति में हस्तक्षेप करना न्यायालयों का काम नहीं है।"

इसलिए, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अधिकारियों और जेसीओ और अन्य रैंकों के बीच पूर्व सैनिकों का उप-विभाजन इच्छित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित है। उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा दायर लिखित बयान में संक्षेप में उल्लिखित और निजी प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा लिखित बयान में विस्तृत कारणों के लिए, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, उपविभाजन मनमाना नहीं है। यह अत्यंत उचित है. अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी में निहित निष्पक्षता की व्यापक अवधारणा राज्य को समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखने और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों को प्राथमिकता देकर सकारात्मक कार्रवाई करने का आदेश देती है। व्यक्ति या प्रभाव उन पर बाधाएं अधिक लाभप्रद हैं

(1) ए.जे.आर. 1970, एस.सी. 35.

वास्तविक समानता लाने के लिए रखा गया। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, हालांकि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है, वास्तविक असमानताओं को दूर करके और समुदाय के कमजोर वर्ग को अधिक शक्तिशाली वर्ग के साथ समानता के आधार पर रखकर व्यापक आधार पर समानता उत्पन्न करने के लिए गणना की जाती है ताकि समुदाय के प्रत्येक सदस्य को लाभ मिल सके। अपनी प्राकृतिक संपदा का पूरा उपयोग करने के समान अवसर का आनंद लें। [परदीप बनाम भारत संघ (2), और जगदीश बनाम भारत संघ (3) देखें]।

(7) राम रतन लेख और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4) में विचार करने के लिए एक बहुत ही समान प्रश्न सामने आया। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में, राज्य सरकार ने मई, 1975 में निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे की 50 प्रतिशत रिक्तियां बाल्मीकि और मजहबी सिखों, यदि उपलब्ध हों, को पहली प्राथमिकता के रूप में देने का आदेश दिया गया था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार. इन निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी क्योंकि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच एक और वर्गीकरण

बनाने की प्रवृत्ति रखते थे। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया और ऐसा करते हुए, साधु सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) में एक अन्य खंडपीठ के फैसले को अलग कर दिया और मिस रीता कुमारी बनाम भारत संघ और अन्य पर भरोसा किया, (6). वही निर्देश फिर विचार के लिए आये। ऊपर उल्लिखित दो डिवीजन बेंचों में कुछ मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, मामले को कंवलजीत सिंह सिद्धू और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7) मामले में पूर्ण बेंच को भेजा गया था। पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीश राम रतन लेख के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों के समान निष्कर्ष पर पहुंचे। मई, 1975 के निर्देशों को चुनौती अस्वीकार कर दी गई। पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए, डी.एस. तेवतिया, जे. (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) ने केरल राज्य में कृष्णा अय्यर, जे. (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) और एक अन्य बनाम एन.एम. थॉमस और अन्य, (8) के निम्नलिखित अंश उद्धृत किए):

“यहाँ और अन्य जगहों के अनुभव के आलोक में, मुझे ऐसा लगता है कि ‘आरक्षण’ का ख़तरा तीन गुना है। इसके फायदे,

(2) ए.आई.आर. 1984, एस.सी. 142(एच

(3) ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 820.

(4) 1978, एसएलडब्ल्यूआर। 69.

(5) सी.डब्ल्यू.पी. 1976 का 2475, 6 जुलाई 1976 को निर्णय लिया गया।

(6) ए.आई.आर. 1973, एस.सी. 1050।

(7) 1980 (3) एस.एल.आर. 34.

(8) ए.आई.:आर, 1976, एस.सी., 490।

आम तौर पर उन्हें 'पिछड़ी' जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिया जाता है, इस प्रकार कमजोरों में से सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखा जाता है और भाग्यशाली परतों को पूरा केक खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ”

“वास्तव में, ए.एन. सिन्हा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना द्वारा किए गए शोध से हरिजनों के बीच एक दोहरे समाज का पता चला है, एक छोटा सा अभिजात वर्ग लाभ उठा रहा है और गहरे स्तर के लोग विशेष रियायतों से दूर सो रहे हैं। उनके लिए, कला. 46 और 335 एक 'नेक रोमांस' बने हुए हैं, बोनान्ज़ा, 'उच्च' हरिजन के लिए जा रहा है।

(8) उपरोक्त उद्धरण में क्या संक्षेप में बताया गया है टिप्पणियाँ, अधिकारियों की उप-श्रेणियों, जेसीओ और अन्य रैंकों पर समान रूप से लागू होती हैं। यदि अनुच्छेद 14 में व्याप्त निष्पक्षता की अवधारणा का

कोई अर्थ है, तो विवादित उप-वर्गीकरण को निष्पक्ष, उचित माना जाना चाहिए और इसका उद्देश्य दो वर्गों के बच्चों को अवसर की समानता प्रदान करना है।

(9) सिद्धांत और मिसाल दोनों पर, इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व सैनिकों की श्रेणी में एक ओर अधिकारियों के बच्चों और दूसरी ओर जेसीओ और अन्य रैंकों के बीच उप-वर्गीकरण उचित है। , निष्पक्ष और वैध, इस तरह के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ संबंध रखता है।

(10) उपरोक्त कारणों से, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)